

## जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण

### प्रलिस के लयः

उप-वर्गीकरण, राष्ट्ररीय अनुसूचतऱ जातऱ आयोग, राष्ट्ररीय पछऱडा वरग आयोग (NCBC), अनुसूचतऱ जनजातऱ

### मेन्स के लयः

जातऱीं का उप-वर्गीकरण, सुभेदु वरगों की रकषा एवं बेहतरी के लयऱ गठतऱ तंत्र, वधऱऱ, संसूथान एवं नकऱय

[स्रोतः द हदऱऱ](#)

## चरूा में कूरुं?

भारत के प्रधानमंत्रऱ ने अनुसूचतऱ जातऱ (SC) के अंतरगत आने वाले सबसे पछऱडे समुदायों की पहचान तथा उनकी सहायता करने की प्रतऱबऱधता वूकूत की है, इसने [अनुसूचतऱ जातऱ \(SC\)](#) के भीतर [उप-वर्गीकरण](#) के मुदुदे को चरूा में ला दऱऱा है ।

- इस नरऱणय के परणऱमसूवरूप उप-वर्गीकरण की वैधता, चुनौतऱीं तथा संभावतऱ प्रभाव पर चरूा शुरु हो गई है ।

## जातऱीं के भीतर उप-वर्गीकरण कूा है?

### ■ परचऱयः

- जातऱीं के भीतर उप-वर्गीकरण आरकषण तथा सकारातूक कारूरवाई के लयऱ [अनुसूचतऱ जातऱ \(SC\)](#), [अनुसूचतऱ जनजातऱ \(ST\)](#) और [अनूय पछऱडा वरग \(OBC\)](#) की मूजूदा शूरेणऱीं के भीतर उप-समूह बनाने की प्रकूरऱऱा को संदरूभतऱ करतऱा है ।
- उप-वर्गीकरण का उदुदेशू अंतर-शूरेणी असमानताओं का समाधान करना तथा समाज के सबसे वंचतऱ एवं हाशऱऱऱ पर रहने वाले वरगों के बीच लाभ व अवसरों का अधकऱ नूयायसंगत वतऱरण सुनशूचतऱ करना है ।

### ■ उप-वर्गीकरण की वैधताः

- ऐतऱहासकऱ प्ररूयासः
  - सरूवूचू नूयायालय तक पहुँचे इस मामले में कानूनी चुनौतऱीं का सामना कर रहे पंजाब, बहऱर तथा तमलऱनाडु जैसे राजूयों ने उप-वर्गीकरण का प्ररूयास कऱऱऱा है ।
- संवैधानकऱ दुवधऱऱः
  - भारत के [सरूवूचूचू नूयायालय](#) ने ई.वी. चनऱनैया बनाम आंधूर प्ररूदेश राजूय और अनूय, 2004 के मामले में कऱऱा कऱेकेवल संसद के पास SC तथा अनुसूचतऱ जनजातऱीं (ST) की सूची बनाने एवं अधसूचतऱऱ करने का अधकऱर है ।
  - हालूँकऱ पंजाब राजूय और अनूय बनाम दवदऱर सहऱ एवं अनूय, 2020 के एक अनूय मामले में पॉच-नूयायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कऱऱ राजूय पहले से ही अधसूचतऱऱ SC/ST की सूचऱऱीं में "छेडूछाडू" कऱऱऱऱ बना लाभ की मात्रा पर नरऱणय ले सकते हैं ।
    - वरूष 2004 और 2020 के फैसलूँ के बीच वरऱऱाधाभास के कारण वरूष 2020 के फैसले को बडी बेंच को भेजा गया है ।
  - संवधऱन के [अनुचूछेद 16\(4\)](#) में यह अधकऱर दऱऱऱा गया है कऱऱ राजूय अनुसूचतऱऱ जातऱ और अनुसूचतऱऱ जनजातऱ के लयऱ पदोननतऱ के मामलूँ में आरकषण के लयऱ कूई प्ररूावधान कर सकतऱा है, यदऱवे राजूय के तहत सेवाओं में प्ररूयाप्त रूप से प्रतऱनऱधऱतऱव नही करतऱे हैं ।

## जातऱीं के भीतर उप-वर्गीकरण की आवश्यकता कूरुं है?

- वूयवसाय, शकऱषा, आय, सामाजकऱ सूथतऱऱऱ और कषेतूरीय ववऱधऱता जैसे कारकूँ के आधार पर SC, ST और OBC शूरेणऱऱीं के भीतर एक महतूतूवपूरूण भनऱनता और ववऱधऱता है ।
  - SC, ST और OBC शूरेणऱऱीं के भीतर कूछ प्ररूमुख एवं प्ररूभावशाली उप-समूहूँ के अनुपातहीन तथा वषऱम प्रतऱनऱधऱतऱव के प्ररूमाण हैं,

जनिहोंने कमज़ोर तथा अधकि पछिडे उप-समूहों को पीछे छोडते हुए आरक्षण के लाभ के बडे हसिसे पर कब्ज़ा कर लिया है ।

- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर वभिन्न उप-समूहों, जैसे कि **तेलंगाना में मडगिा**, बिहार में पासवान और उत्तर प्रदेश में जाटव द्वारा नषिपक्ष तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चिती करने के लिये उप-वर्गीकरण एवं अलग कोटे की मांग की जा रही है ।

## जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की चुनौतियाँ क्या हैं?

- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर वभिन्न उप-समूहों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर **वशि्वसनीय तथा अद्यतन डेटा की कमी है**, जो उप-वर्गीकरण के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक आधार को बाधति करता है ।
- SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर प्रमुख एवं प्रभावशाली उप-समूहों से **कानूनी तथा राजनीतिक प्रतिक्रिया** की संभावना है, जो उप-वर्गीकरण व आरक्षण लाभ के अपने हसिसे में कमी का वरिोध कर सकते हैं ।
- SC, ST व OBC श्रेणियों के भीतर और अधकि वखिंडन तथा वभिजन का खतरा है, जो उनकी सामूहिक पहचान एवं एकजुटता को कमज़ोर कर सकता है, साथ ही उनके राजनीतिक, सामाजिक सशक्तीकरण को कमज़ोर कर सकता है ।

## आगे की राह

- **SC, ST और OBC के भीतर उप-समूहों की जनसंख्या एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक व्यवस्थित एवं अद्यतन डेटा संग्रह प्रक्रिया सुनिश्चिती करना ।**
  - साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिये एक ठोस आधार प्रदान करने हेतु संपूर्ण जातजिनगणना आयोजति करना ।
- **सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के व्यापक लक्ष्यों के साथ जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को संतुलति करने एवं यह सुनिश्चिती करने की आवश्यकता है कि उप-वर्गीकरण समानता तथा गैर-भेदभाव के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता हो ।**
- सामाजिक न्याय और लाभों के समान वतिरण को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर ज़ोर देते हुए उप-वर्गीकरण के पीछे के तर्क को स्पष्ट करने हेतु संचार रणनीतियाँ विकसित करना ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति संगठनों/नकियाँ पर वचिर कीजयि: (2023)

1. राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग
2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
3. राष्ट्रीय वधि आयोग
4. राष्ट्रीय उपभोक्ता वविद नविरण आयोग

उपर्युक्त में से कतिने सांवधानिक नकियाय हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (a)